months as compared to the years 1977, 1978 and 1979;

(b) whether some multinationals producing these items are responsible for this spurt; and

(c) what action is proposed to be taken to curb the price rise so as to bring it within the reach of poormen?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) and (b). During the last three months (March-May, 1980), the wholesale price indices for detergents, tooth paste and processed milk have remained generally steady whilst in the earlier years their indices have either remained steady or have gone up. However, the wholesale price period has edible oils during the same period has gone up by 1.7 per cent which is less than the increase of 11.5 per cent during the corresponding period in 1979 but more than the increase in 1978. In 1977 there was a marginal fall in indices of edible oil during the reference period. In the case of pulses the increase (8.5 per cent which is less than the indices during the last three months of the current year has been higher than the increases that have taken place in earlier years.

The index for soap during the past three months has moved up by 7.4 per cent and is higher than the increases that have taken place in earlier years.

Edible oils are produced by very large number of units in the country, both in the organised and unorganised sectors and the share of multinational corporations would be very small in the total production. Soaps are being produced both in the large as well as small scale sectors. The role of multinationals in the price increase of soaps will be looked into. The wholesale price index for shampoos is not available.

(c) Efforts are being made to increase the production of oilseeds and pulses. Import of edible oils is being continued and during the first seven months of the current oil year (Nov. 1979-May. 1980) about 1.60 lakh tonnes of imported edible oils have been released to the States for distribution through the public distribution system. The import of pulses continues to be under Open General Licence.

The State Governments have been requested from time to time to enforce the various provisions of the Essential Commodities Act, 1955 and the orders issued thereunder including Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, vigorously. Similarly they have also been asked to implement the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980.

उचित दर दुकानों पर आवश्यक पदार्थों की सप्लाई

752. **श्री मूल चन्द डागा:** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर आवश्यक पदार्थों की ठीक समय पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि इस प्रकार की कोई योजना तैयार नहीं की गई है तो इसके कब तक तैयार किए जाने की आशा है और सरकार कब तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग को यह लाभ मुहय्या करवाने की स्थिति में होगी।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस देश में लगभग तीन दशकों से कार्य कर रही है। इस प्रणाली की राज्य सरकारों, सम्बन्धित मंत्रालयों और भारत सरकार के अभिकरणों के परामर्श से निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। इस प्रणाली का उद्देश्य, ग्रामीण

तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों को अपने अन्तर्गत लाने का है। देश में, इस साम्य विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 2,47,470 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आम तौर पर खाद्यान्नों, चीनी, खाद्य तेलों, नियंत्रित कपड़ों तथा मिट्टी के तेल का वितरण किया जाता है। सरकार देश में इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा इसे पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से प्राप्त ऋण में से माल का खरीदा जाना

753. **श्री मूल चन्द डागा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत को इस शर्त पर ऋण देते हैं कि वह इस ऋण से उस देश से माल खरीदेगा:

(ख) क्या इन वस्तुओं को उस समय विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से ड्योढ़ अथवा दो गुने मूल्यों पर माल खरीदा जाता है;

(ग) क्या ऐसा इस कारण से है कि सार्वजनिक उपक्रमों में पूंजी निवेश तथा सामान्य लागत अपेक्षाकृत अधिक हैं जिससे उनमें घाटा होता है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस कारण घाटा न होकर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बरोट): (क) जो देश इस शर्त से बधें हुए ऋण देते हैं कि वस्तुएं तत्संबंधी देशों से मंगानी होंगी वे देश आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की दशा में ऐसा प्रतिबंध थोड़े से मामलों में ही लगाया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा चांदी का जब्त किया जाना

754. **श्री मूल चन्द डागा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गत 6 महीनों में भारत से बाहर तस्करी को जा रही कितनी चांदी जब्त की और उसका मूल्य क्या है;

(ख) चांदी की भारत से बाहर तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) चांदी के बदले में भारत में तस्करी से लाई जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट): (क) दिसम्बर, 1979 से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने भारत से तस्कर निर्यात की जा रही लगभग 7.27 करोड़ रुपये मूल्य की कुल लगभग 22.57 मीट्रिक टन चांदी पकड़ी।

(ख) भारत से चांदी का तस्कर-निर्यात रोकने के लिए, तस्करी के लिए सुगम सभी क्षेत्रों में, जिनमें हवाई अड्डे भारत का पश्चिमी समुद्रतट और भू-सीमाएं शामिल हैं, तस्करी निवारक कार्यवाहियां तेज कर दी गई हैं। सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय 4-ख के उपबन्धों में निहित, चांदी रखने, लाने ले जाने और बेचने संबंधी नियामक उपबंधों को, जो पश्चिमी समुद्रतट और तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी के समुद्रतट के साथ साथ 50 किलोमीटर की पट्टी पर पहले ही लागू थे। अब 27 मार्च, 1980 से भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमाओं के साथ-साथ 50 किलोमीटर की पट्टी पर भी लागू कर दिया गया है।

(ग) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, देश में चोरी-छिपे लायी जाने वाली मुख्य मदें ये हैं:-- कलाई घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्र और इलैक्ट्रानकीय माल।